Scientific Organisations and other connected organisations, to review the progress made thereunder and to consider proposals fort the sanction of grant-in-aid for conducting research connected with the sugar industry and other related matters.

भारतीय खाद्य निगम को मजदूरों की सप्लाई

1436. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारतीय खाद्य निगम को मजदूरों की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों की संख्या कितनी है और इन ठेकेदारों द्वारा अब तक भारतीय खाद्य निगम को अनुमानत: कितने मजदूरों की सप्लाई की गई है ; और

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ठेके के आधार पर काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन व श्रम से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने कुल 1500 डिपुओं में से 702 डिपुओं में हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार सीधे ही नियुक्त किए हैं । इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों की खरीफ और रबी वसूली के दौरान मंडियों में ठेकेदारों की मौसमी नियुक्तियां भी की जाती हैं । कार्य के भार पर निर्भर करते हुए, ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए श्रमिकों की संख्या सामान्यतया प्रति दिन 50,000 से 1,00,000 व्यक्तियों के बीच भिन्न-भिन्न होती है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ठेकेदारों के साथ निष्पादित ठेकों के उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित कर न्यूनतम वेतन और अन्य अनुमेय सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं ।

Production by Sugar Mills in Uttar Pradesh

1437 .SHRI ASHWANI KUMAR : Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the sugar mills currently operating in Uttar Pradesh are only to draw 33 per cent of the total available cane;

(b) whether this drawal percentage is less than the national average; if not, the extent therof; and

(c) what steps Government propose to take to increase the percentage of drawal of Uttar Pradesh to bring it to the national average?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) and (b) As per the figures of 1990-91 season complied on a provisional basis, it is seen that the drawal percentage of sugarcane by the sugar factories in Uttar Pradesh was 31.6% as against the national average of 50.9%.

(c) Government had issued a number of licences for setting up of new sugar factories and expansion in the capacities of existing sugar factories in the State of Uttar Pradesh during the 7th Five Year Plan period. Government had also announced an incentive scheme for early crushing according to which sugar production achieved during the period 01-10-1991 to 15-11-91 would be entitled to freesale at 72%, as against the normal 55%, so as to induce sugar factotries to commence early crushing and thereby crush more sugarcane during the season.

विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण

1438. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) खाद्य मंत्रालय के अधीन दो उपक्रम अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम हैं । इन उपक्रमों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गेहूं का आयात

1439. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1992 के "द इक्नामिक टाइम्स" में "व्हीट इम्पोर्ट मूव फेसेज हर्डल्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों से गेहूं का आयात करने के लिए फरवरी, 1992 के मध्य तक कोई समझौता नहीं हो पाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ भेजा गया प्रतिनिधि मंडल वापस आ चुका है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) जी हां ।

(घ) प्रतिनिधि मंडल के दौरे पर लगभग 4.37 लाख रुपए (होटल प्रभारों को छोड़कर) का अनुमानित व्यय हुआ था ।

Requirement of wheat, rice, and oils of states

1440. SHRI PROMOD MAHAJAN: Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what are the demands made by different States for the quota of wheat, rice and oil ; and

(b) what is the reaction of Government to these demands State-wise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) and (b) Only some States/UTs send demands for monthly allocations of rice and wheat for the Public Distribution System. A statement showing the States from whom demands were received for the month of March, 1992 is attached. (*See below*).

No demands were invited from the State Governments/UTs for allocation of imported edible oil for the oil year 1991-92 (November—October).

The allocations of rice and wheat from the Central Pool are made on a month basis taking into account the stock in the Central Pool, seasonal availability, offtake trend, relative needs of States/UTs and other related factors.

Allocations of imported edible oils are also made to the States/UTs on a month to month basis depending upon the availability of stocks with STC and after assessing the requirement of each State/UT.